Economics उदारीकरण Libearlisation XI 9.A

Dr. Vinod Baitha
Marwari college Darbhanga

भारत सरकार द्वारा 24 जुलाई 1991 आर्थिक सुधार हेतु, आर्थिक संकट से बचने के लिए, आर्थिक संकट से देश को निकालने के लिए, आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए, आर्थिक सुधार Economic Reforms आर्थिक नीति में अनेक नीतिगत उपाय कीए गए, जिसमे उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण महत्वपूर्ण किरियाँ थी जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में अनेक सुधार हुए। उदारीकरण सरकार के नियमों के दबाव को संदर्भित करता है। भारत में उदारिकरण लगातार जारी होने वाले वित्तीय सुधारों को दर्शाता है। उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा लेना जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। उदारीकरण के सारी क्रियाएँ शामिल है। जिनके द्वारा किसी देश के आर्थिक विकास में बाधा पहुँचाने वाली आर्थिक नीतियों, नियमों, प्रशासनिक नियंत्रणों, प्रक्रियाओं आदि को समाप्त या उनमे शिथिलता दी जाती है।

नयी आर्थिक नीति की अपनी अनेक विशेषताएँ है जो अभी तक चली आ रही नीति से इसकी भिन्नता पर प्रकाश डालती है। साथ ही राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए नयी दिशाएँ निर्धारित करती है। उदारीकरण व्यवस्था से अभिप्राय उद्योग तथा व्यापार को अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त करके अधिक प्रतिस्पर्धा योग्य बनाना है। आर्थिक उदारीकरण विशेष रूप से सभी व्यक्तियों को अपनी आवश्यकतानुसार निजी आर्थिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगी रुकावटों और नियंत्रणों को हटाना चाहिए। वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण उत्पादकों द्वारा किया जाना चाहिए, निजी उपक्रम एवं पूँजी को बढ़ती मात्रा में निवेश का अवसर प्रदान करना चाहिए, निजी उपक्रम एवं पूँजी पर लगी रुकावट एवं नियंत्रणों को हटाना चाहिए

उदारीकरण नीति के अन्तर्गत अर्थव्यवस्था के बाहरी क्षेत्र से संबंधित है अर्थव्यवस्था के भीतर आने वाले एवं बाहर जाने वाले प्रवाहों को अधिक सरल और सुविधा जनक बना दिया गया है। उदारिकरण में साल भर के स्थान पर अब तीन साल तक के लिए व्यापार नीति की घोषणा की जाती है। इससे आयात और निर्यात के संबंध में निर्णय लेने के लिए स्थायी आधार मिल गया है। आयात के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए हैं वे गुणात्मक महत्व के है। अधिकांश आयातों पर से मात्रा प्रतिबंध हटा लिए गए है। जैसे आयात कोटा आदि। अब आयात विनियमन के लिए टैरिफ और वित्तीय उपकरणों का सहारा लिया जाता है। एक अन्य बात जिसका कम महत्व नहीं है, यह है कि नयी नीति के अन्तर्गत पूँजी माल मध्यवर्ति वस्तुए तथा उन्नत तकनीकि में सुधार लाने एवं विश्वप्रतियोगिता में टिक सकने वाली निर्यात वस्तुओं के उत्पादन के किलसीले में बाधक दबाव डाला जा सके। इसी बात को लेकर विदेशी और घरेलु उद्यमों के बीच

उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। विदेशी उद्यमों को निवेश व्यापार एवं तकनीक के क्षेत्र में आकर्षित करने के लिए अनेक उदारपूर्ण सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है। निर्यात के क्षेत्र में ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे की नये निर्यातक प्रवेश कर सके, प्रतियोगिता जोड़ पकड़ सके तथा अधिक मात्रा में निर्यात की जा सकने वाली वस्तुओं को बढ़ावा मिले।

उदारीकरण नीति में घरेलू उत्पादन तकनीकि में अधिक से अधिक सुधार कर के अधिक से अधिक उत्पादन क्षमता का विकास करने का अवसर मिलना चाहिए। रोजगार के अवसरों में अधिक से अधिक वृद्धि होना चाहिए। वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता में विश्वस्तरीय सुधार होना चाहिए। उदारीकरण अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा के योग्य बनाना चाहिए।

नयी आर्थिक नीति में उदारीकरण आर्थिक सुधारें हेतु अनेक सुझाव अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु किए गए हैं इन आर्थिक सुधारों में नयी औद्योगिक नीति 1991 के अन्तर्गत बहुआयामी औद्योगिक नीति सुधारें द्वारा संरक्षणवाद को समाप्त कर प्रतिस्पर्द्धात्मक वातावरण का सूत्रपात किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा विनियोग के लिए सुरक्षित क्षेत्र को 17 से क्रमशः कम कर के 2 तक लाया गया है। इसके अतिरिक्त 5 उद्योगों को छोड़कर शेष सभी प्रकार के औद्योगिक उपक्रमों को लाइसेंस लेने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। उद्योगों को बिजली संबंधी अनेक छूट प्रदान की गयी है। देश में औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में नये उद्योगों के लिए भारत में कहीं भी विद्युत उत्पादन करने के लिए पाँच वर्ष तक की कर की छूट लागू की गयी है। उदारीकरण में एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार अधिनियम में संशोधन किए गए हैं। उदारीकरण में लघु उद्योग की निवेश की सीमा को बढ़ाया गया है। नयी आर्थिक नीति के अनुसार लघु उद्योगों के निवेश की सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है। विदेशों से कच्चे माल और मशीनरी का मुक्त आयात की व्यवस्था की गयी है। अब कम्पनियाँ जा वही विदेशी चीजों को खुले बाजार से खरीद सकती हैं इसके लिए सरकार से कोई अनुमति की जरूरत नहीं है। यह उदार नीति बाजार में प्रतियोगिता को पैदा करती है। जिससे कुशलता से बढ़ोतरी होती है। उदारीकरण में अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु टेक्नोलॉजी आयात पर विशेष छूट दी गयी है। भारतीय उद्योगों को नयी टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराने के लिए नयी औद्योगिक नीति में यह प्रावधान किया गया है। उच्चतम प्राथमिकता वाले उद्योगों को समझौता करने की कोई आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है। वित्तीय संस्थानों को स्वतंत्रता प्रदान की गयी है। वित्तीय संस्थान जैसे बैंक आदि अब जमा राशि अथवा ऋण आदि पर ब्याज दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है इससे उनके व्यापार और लाभ में सहायता मिलेगी। उदारीकरण व्यवस्था में आर्थिक सुधार हेतु कर की दरों में कमी की गयी है। जिससे आयातित सामग्री पर कर की दरें कम हो सकें।

नयी आर्थिक नीति में आर्थिक सुधार हेतु उदारीकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इससे अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है। वर्तमान समय में उदारीकरण व्यवस्था में सरकार द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया जाना चाहिए। उत्पादन व्यवस्था में सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए उत्पादन इकाइयों को आरंभ करने की स्वतंत्रता रहनी चाहिए। विदेशी निवेश का खुला आगमन होना चाहिए। नयी मशीन तथा नयी तकनीकों का उपयोग तथा उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए इससे उदारीकरण व्यवस्था को बल मिलेगा। उदारीकरण व्यवस्था में सामाजिक कल्याण की उपेक्षा एवं स्वहित भावना को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। एकाधिकार की भावना में वृद्धि नहीं होना चाहिए। आर्थिक असमानता में वृद्धि नहीं होना चाहिए।

इस तरह नयी आर्थिक नीति में उदारीकरण एक महत्वपूर्ण कदम है इससे भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है।

Scanned by CamScanner